(3) *Selection of Areas*: The areas for operating the scheme are selected by the GIC in consultation with the State Governments. The premium rate as well as indemnity for the selected crops is uniform for all insured farmers within each basic unit of area selected irrespective of actual yield per borrower.

(4) *Basis of Premium and Indemnity*: (a) Premium and indemnity rates for each selected crop and season in each selected areas are determined on the basis of crop cutting experiments for the last 10 years. The Scheme of Insurance does not provide 100 per cent compensation in the event of loss of crop and the farmers are required to bear a portion of the loss. Calculations made on the basis of corp cutting data in respect of Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Kerala have shown that full indemnity in the case of crop losses is not feasible since mnity would be anywhere upto 30 per premium rates for securing full indecent at which rate farmers cannot afford to pay premium. Therefore, premium and indemnity tables have been worked out on the basis that farmers will bear a portion of loss, which is called non-indemnifiable limit, which varies from 20 per cent to 50 per cent. On this basis there will be a number of areas where premium rate are well within 5 per cent and many other areas where premium ranges from 5 per cent to 10 per cent of Sum insured. Past experience in operating crop insurance scheme and the data of 10 years crop yield based on NSS indicated the percentage of 5-10 per cent premium to be sufficient to cover the incidence of indemnity payable. Indemnity to any farmer becomes payable only if the average yield in the insured areas falls below the guaranteed yield

(5) *Role of the State and Central Government*: The State Governments are co-insurers with G.I.C. and share the premium and indemnity to the extent of 25 per cent. They are also responsible for arrangements for estimation of crop yields through crop cutting experiments. The Government of India has agreed to subsidies the premium payable by the small and marginal farmers in the special programme areas like I.R.D. upto 25 per cent, the State Government sharing another 25 per cent.

गेहूं और चने का समर्थन मूल्य

2585. **श्री कुंभा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं और चने के कितने समर्थन मूल्य की वर्ष-वार, सिफारिश की है ;

(ख) क्या इस बारे में गत पांच वर्षों के दौरान समिति की सिफारिशों को पूरी तरह मान लिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो किस वर्ष ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) 1977–78 (फसल वर्ष) से गेहू और चने के अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । वर्ष 1978–79 1979–80 और 1981–82 के लिये सरकार द्वारा गेहूं के निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य और 1978–79 और 1979–80 के लिये चने के निर्धारित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य वही थे, जिनकी कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी । सरकार द्वारा 1977–78 और 1980–81 की फसल के लिये गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य और 1977–78 के लिये चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्य स्तर से अधिक

निर्धारित किये गये थे । इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराना था । वर्ष 1980–81 और 1981–82 में सरकार ने बाजार मूल्य का विद्यमान स्तर ऊंचा होने के कारण चने का समर्थन मूल्य घोषित करना आवश्यक नहीं समझा :

विवरण

गेहूं और चने के अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य

(प्रति क्विंटल रुपयों में)

फसल वर्ष	अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य	
	जैसी कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई है ।	जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया गया है ।
गेहूं		
1977–78	110.00	112.50
1978–79	115.00	115.00
1979–80	117.00	117.00
1980–81	127.00	130.00
1981–82	142.00	142.00
चना		
1977–78	120.00	125.00
1978–79	140.00	140.00
1979–80	145.00	145.00
1980–81	165.00	एन०ए०
1981–82	227.00	एन०ए०

एन० ए० घोषित नहीं किये गये हैं ।